



आय में अंतर कम करने पर जोर

रिपोर्ट में यह बात रेखांकित की गई है कि देश में आय वितरण की पहले से ही असंतुलित स्थिति धीरे-धीरे और बदतर होती जा रही है। हालांकि रिपोर्ट में जिन आंकड़ों के सहारे यह बात कही

गई है, उनसे तस्वीर ज्यादा असंतुलित नहीं नजर आती।

राधा वर्मा।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में आया यह सुझाव महत्वपूर्ण है कि देश में आय की जबर्दस्त विषमता को कम करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम और शहरी रोजगार गारंटी योजनाएं शुरू की जाएं। रिपोर्ट में यह बात रेखांकित की गई है कि देश में आय वितरण की पहले से ही असंतुलित स्थिति धीरे-धीरे और बदतर होती जा रही है। हालांकि रिपोर्ट में जिन आंकड़ों के सहारे यह बात कही गई है, उनसे तस्वीर ज्यादा असंतुलित नहीं नजर आती। मिसाल के तौर पर, इसमें पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) के तीन दौर के रिजल्ट्स के हवाले से बताया गया है कि 2017-18 से 2019-20

तक के तीन सालों में कुल कमाई में आबादी के टॉप 1 फीसदी का हिस्सा 6-7 प्रतिशत था। ज्यादा सटीकता से कहा जाए तो यह हिस्सा तीन वर्षों में 6.14 फीसदी से बढ़कर 6.82 फीसदी हुआ था। अगर कमाई में बढ़ोतरी की बात करें तो इन तीन वर्षों में आबादी के टॉप 1 फीसदी हिस्से की आय 15 फीसदी बढ़ी जबकि आबादी के सबसे निचले 10 फीसदी हिस्से की आय में 1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इन आंकड़ों के बरक्स हम पिछले साल दिसंबर में जारी वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 को रखें तो हालात कहीं ज्यादा गंभीर नजर आते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में देश में कुल आमदनी का 22 फीसदी हिस्सा टॉप एक फीसदी आबादी के खाते में था। टॉप



10 फीसदी आबादी कुल आमदनी के 57 फीसदी हिस्से पर काबिज थी। नीचे की 50 फीसदी आबादी को राष्ट्रीय आय के महज 13 फीसदी हिस्से पर संतोष करना पड़ रहा था। आश्चर्य नहीं कि इस वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट में भारत को दौलतमंद इलीट वाला गरीब और बेहद असमान देश बताया गया था। बहरहाल, ब्योरे में जो भी फर्क हो, निष्कर्ष में कोई अंतर नहीं है।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने भी स्थिति को गंभीर मानते हुए तत्काल आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। हालांकि यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना शुरू करने की बात कोई नई नहीं है। वित्त वर्ष 2017 के आर्थिक सर्वे में तत्कालीन मुख्य वित्तीय

सलाहकार अरविंद सुब्रमणियन की यह सलाह दर्ज की गई थी कि सब्सिडी के लंबे चौड़े खर्च के बदले यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना शुरू की जाए ताकि हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ आमदनी सुनिश्चित की जा सके। बाद में आईएमएफ ने भी फूड और फ्यूल सब्सिडी के बदले यूनिवर्सल इनकम स्कीम शुरू करने के सुझाव पर जोर दिया था। इससे कहीं न कहीं यह आशंका भी बनती है कि प्रस्तावित स्कीम लोगों की आमदनी में अंतर घटाने के बजाय सब्सिडी से छुटकारा दिलाने के उद्देश्यों तक सीमित न रह जाए। मगर मन्त्रंगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना जरूर समय की जरूरत है। इससे जहां असंगठित क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को आजीविका मिलेगी, वहीं इकॉनमी में डिमांड बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है।

घमंडी और आत्मकेंद्रित

अशोक वोहरा।
बुद्ध बोले, "मैं ज्ञानी नहीं हूँ, और इनसान हूँ।
वैसे भी वह ज्ञान किस काम का, जो इतना घमंडी और आत्मकेंद्रित हो कि अपने अतिरिक्त दूसरे की चिंता ही न कर सके? ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति की उलझन दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच व आचरण दोनों बदल गए। कथा का सार यह है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है, जब वह लोक कल्याण में संलग्न हो। उसने सोचा कि इन्हें दुनियादारी के मामलों में पड़ने से क्या लाभ? अपना भगवद् भजन करें और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को भगाएँ, किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुःख उनका अपना दुःख है।
आखिर उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, "महाराज आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना-देना?"

धर्म-दर्शन



संपादकीय

सामरिक जरूरत

ऐसे दौर में जब चीन ने भारत पर जबर्दस्त सामरिक दबाव बनाया हुआ है, क्वाड में भारत की सक्रिय भागीदारी उसकी सामरिक जरूरत है। रूस और चीन की भागीदारी वाले पांच देशों के संगठन ब्रिक्स की उपेक्षा कर क्वाड के साथ मुस्तैदी से खड़ा होना भारत के दीर्घकालीन सामरिक हितों के हक में है। क्वाड के चारों सदस्य देशों का इतनी जल्दी-जल्दी मिलना संकेत देता है कि दुनिया के चारों ताकतवर देश चीन द्वारा पेश की जा रही सामरिक और आर्थिक चुनौतियों का मिल-जुलकर मुकाबला करने के लिए सक्रिय हैं। इस बात की आशंका थी कि यूक्रेन संकट में क्वाड को लपेटने से क्वाड का फोकस हिंद-प्रशांत के इलाके से हट जाएगा। लेकिन भारत की सक्रिय भागीदारी ने यह सुनिश्चित किया कि इस संगठन में इसी इलाके के मसलों पर मुख्य चर्चा हो। इसमें भारत की सक्रिय भागीदारी होना बताता है कि हिंद-प्रशांत इलाके में भारत की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्वाड के गठन के पहले से ही हिंद-प्रशांत के दक्षिण चीन सागरीय इलाके में चीन की दादागीरी के खिलाफ भारत निडर होकर आवाज उठाता रहा है। तोक्यो में जारी साझा बयान में भी इसी बात पर और जोर दिया गया। लेकिन भारत को क्वाड के कंधे की आड़ लेकर नहीं, बल्कि अपने दम पर चीन से मुकाबला करने के लिए अपने आपको आर्थिक और सामरिक तौर पर और सशक्त बनाना होगा।

हिंद प्रशांत के सागरीय इलाके में सारे नियम कानूनों को तोड़ते हुए चीन जिस अंधाधुंध तरीके से मछलियां पकड़ रहा है, वह समुद्री जीवन के लिए तो खतरा है ही, समुद्री पर्यावरण को भी बिगाड़ रहा है।

चीन अपने ही इलाके में अलग-थलग

पूनम पाण्डे।

चार देशों के संगठन क्वाड (अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान) की यूक्रेन संकट की छाया में हुई चौथी शिखर बैठक में जोर चीन की आर्थिक चुनौतियों से मुकाबला करने पर रहा। चीन छोटे देशों को अपने आर्थिक मोहपाश में फांस कर अपना सामरिक जाल फैलाता है। इसी जाल को तोड़ने के इरादे से क्वाड शिखर बैठक में क्षेत्र के 12 देशों को साथ लेकर इंडो पैसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क का एलान किया गया। इस तरह क्वाड ने यूक्रेन संकट पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बदले चीन की आर्थिक और सामरिक चुनौतियों से निपटने पर ही अधिक चर्चा की और टोस कार्यक्रम के साथ संकल्प जाहिर किए।

23-24 मई को तोक्यो में आयोजित शिखर बैठक में आर्थिक क्षेत्र में चीन की महाजनगीरी से निपटने के लिए जो साझा कार्यक्रम घोषित किए गए, अगर उन्हें गंभीरता और सक्रियता से लागू किया जाए तो निश्चय ही चीन के सामरिक और आर्थिक प्रभुत्व को तोड़ने या सीमित करने में कामयाबी मिल सकती है। अगर ऐसा हो गया तो चीन अपने ही इलाके में अलग-थलग पड़ जाएगा। यही वजह है कि चीन ने क्वाड शिखर बैठक पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है।

चीन अपनी आर्थिक ताकत के बल पर ही



दुनिया के छोटे देशों के गैर-जनतांत्रिक नेताओं को नाजायज तरीके से प्रभावित करता है। वह पहले से ही उन देशों को विकास का सपना दिखा कर उन्हें अपने प्रभाव में लाने की रणनीति पर चलता रहा है। इसके अलावा निर्माण उद्योग के क्षेत्र में दुनिया के उद्योगों को जरूरी कच्चा माल और कलपुर्ज आदि सप्लाई करने का एक प्रमुख स्रोत बनने के बाद वह दुनिया पर अपना आर्थिक दबदबा भी कायम करने में कामयाब हुआ है। लेकिन अब क्वाड के चार सदस्य देशों ने इस सप्लाई कड़ी को तोड़ने के इरादे से कई अहम कार्यक्रमों की शुरुआत की है।

चारों देश क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ग्रुप बनाकर सेमीकंडक्टर चिप्स जैसे उच्च तकनीक के कलपुर्जों की सप्लाई पर चीन के एकाधिकार को तोड़ने में परस्पर सहयोग करेंगे। भारत के लिए इन उच्च तकनीक वाले कलपुर्जों की दुनिया को सप्लाई का वैकल्पिक स्रोत बनने की संभावना है। इसके

साथ ही चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई- जो छोटे देशों में सड़क, रेल जैसी ढांचागत परिवहन सुविधाएं बनाती है) के विकल्प के तौर पर क्वाड में इफ्रास्ट्रक्चर कोआर्डिनेशन ग्रुप (क्वाड ढांचागत समन्वय दल) का गठन भी किया गया है। इसके लिए क्वाड की ओर से 50 अरब डॉलर आवंटित किए गए हैं।

इसके अलावा छोटे समुद्र तटीय देशों या द्वीपीय देशों के निकट के सागरीय इलाके से गैरकानूनी तौर पर मछलियां पकड़ने जैसी चीन की हरकतों पर भी लगाम लगाने के इरादे से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। हिंद प्रशांत के सागरीय इलाके में सारे नियम कानूनों को तोड़ते हुए चीन जिस अंधाधुंध तरीके से मछलियां पकड़ रहा है, वह समुद्री जीवन के लिए तो खतरा है ही, समुद्री पर्यावरण को भी बिगाड़ रहा है। चीन की इन गतिविधियों पर काबू पाने के लिए क्वाड ने जो योजना बनाई है, उसमें भारत की अहम भूमिका होगी।

पिछले 14 महीनों के भीतर क्वाड की चौथी शिखर बैठक का होना काफी अहम है। पहली वर्चुअल शिखर बैठक चीन से दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी के बैकग्राउंड में मार्च, 2021 में हुई थी। सितंबर, 2021 में वॉशिंगटन में चारों देशों के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में दूसरी शिखर बैठक हुई थी।

सूडोकू बवताल- 5347		****	
	1		6
		5	
2	3	9	8
6			5
	8	3	
1			4
	7		1
		2	3
5		6	

अपना ब्लॉग

आकुस की स्थापना से भी घबराया चीन

मोहन। चीन क्वाड ही नहीं, आकुस की स्थापना से भी घबराया हुआ है। तोक्यो बैठक के दो दिन पहले चीन ने जो प्रतिकूल टिप्पणी की है, उससे सब पता चल जाता है। इससे लग रहा है कि आर्थिक, सामरिक और सुरक्षा क्षेत्र में चार बड़े देशों की यह एकजुटता चीन के सपनों पर पानी फेर देगी। चीन का 2047 तक दुनिया का नंबर एक देश बनने का लक्ष्य है। क्वाड की इसी संभावित चुनौती से चिंतित होकर चीन ने रूस के साथ दोस्ती गहरी की। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन पर सैनिक अतिक्रमण करने के बाद रूस पूरी दुनिया से अलग-थलग हो गया है, वह चीन के आर्थिक और सामरिक मंसूबों को हासिल करने में सहायक नहीं हो पाएगा। इसके बाद मार्च, 2022 में फिर वर्चुअल शिखर वार्ता आयोजित हुई। इसके दो महीने बाद ही तोक्यो में चारों शिखर नेताओं की सशरीर मौजूदगी में हुई क्वाड शिखर बैठक ने यह आभास दिया कि ये देश दुनिया में शांति और स्थिरता को खतरा पहुंचाने वाली ताकतों की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए कमर कस कर एकजुट होंगे।

